निक्षेप किए हैं, उन्होंने इस आशय की शिकायतें की हैं, यदि हां, तो उनके मंत्रालय को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) : भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार लॉकरों का आबंटन करने पर बैंकों को आवेदक से, जिन्हें लॉकर आबंटित किए गए हैं, निक्षेप की अनुमति दी गयी है ताकि लॉकर के किराये की रकम को जमा राशि पर देय ब्याज से वसूल किया जा सके। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर ने सूचित किया है कि उसने नई दिल्ली की जनकपुरी शाखा सहित अपनी सभी शाखाओं को एक निश्चित जमा राशि, जिस पर ब्याज की राशि लॉकर के वार्षिक किराये और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो, के लिए लॉकर धारकों से ब्याजवाली लॉकर जमा राशियों को प्राप्त करने की अनुमति देते हुए आवश्यक निर्देश जारी किये हैं।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने यह भी सूचित किया है कि उन्हें उन लोगों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जिन्होंने लॉकर प्राप्त करने के लिए लॉकर निक्षेप किया है।

Recovery of Bank Loans From Farmers in Madhya Pradesh

746. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal under consideration to defer the recovery of bank loans from the farmers of Madhya Pradesh in view of the serious drought conditions in the State ;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether Government also propose not to charge any interest on bank loans from the farmers of Madhya Pradesh for the whole period during which the State is in grip of drought; and

(d) if the answers to parts (a) and (c) above are in the Negative what are the reasons therefor, and how Government propose to give relief to the drought affected farmers of Madhya Pradesh ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (d) The Commercial Banks have standing instructions from Reserve Bank of India (RBI) for providing relief and rehabilitation assistance to the persons affected by natural calamities such as droughts, floods, cyclones, etc. The above instructions are uniformly applicable to all States/Union Territories including Madhya Pradesh. The guidelines envisage, *inter-alia* (i) conversion of short term production loans into medium term loans; (ii) rescheduling/postponement of existing term loans instalments, (iii) provision of additional need based crop/investment loans, etc. In terms of the above guidelines, in the case of small and marginal farmers, interest on short-term loans which has been converted into term loan may be postponed and recovered at the time of next harvesting/ marketing season. There is no compounding of the intrest outstanding of the interest outstanding on the short term loan in such cases. For other farmers, who have an established capacity to pay the interest due on short-term loans, recovery of such interest is necessary before the grant of conversion facilities.

747. [Transferred to the 8th May 1992]

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के अधीन की गई कार्यवाही

748. श्री ईशदत्त यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के अधीन कितने मामलों की जांच की गई ;

(ख) इस जांच के माध्यम से पता लगाये गये व्यापार के मूल्य का राज्यवार ब्यौरा क्या है।

(ग) बम्बई में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन मार्च के महीने में किए

गए घोटालों के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा जिन व्यक्तियों के खिलाफ ऐसी सूचनायें प्राप्त हुई, उनके नाम क्या-क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रामेश्वर ठाकुर : (क) और (ख) वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान जांच किए गए मामलों की संख्या जब्त की गई विदेशी मुद्रा और भारतीय मुद्रा की राशि दर्शाने वाले सांख्यिकीय आंकड़े क्षेत्रवार नीचे दिए गए हैं :—

		बम्बई	कलकत्ता	दिल्ली	जालन्धर	मद्रास
1. जांच किए गए मामलों की संख्या	1989	1962	1922	1606	274	2288
	1990	1857	1636	1681	286	1927
	1991	2008	1107	2151	358	1687
2. जब्त की गई विदेशी मुद्रा की राशि	1989	110.83	8.95	40.14	12.40	19.66
	1990	66.38	0.49	26.75	5.20	37.59
	1991	76.30	20.86	120.69	5.57	91.43
(रु० लाखों में)						
3. जब्त की गई भारतीय मुद्रा की राशि	1989	255.72	114.59	100.56	19.31	311.50
	1990	187.07	27.16	40.33	9.47	378.82
	1991	542.14	131.07	53.35	20.19	391.46
(रु० लाखों में)						

आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते हैं, बल्कि क्षेत्रवार रखे जाते हैं ।

(ग) और (घ) जब कभी कोई शिकायत आसूचना प्राप्त होती है विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के अन्तर्गत समुचित कार्रवाई की जाती है । प्रक्रिया तेज की जाती है प्राप्त की गई शिकायत आसूचना का ब्यौरा प्रक करना जनहित में वांछनीय नहीं होगा ।

Salary Saving Scheme for Employees of Hesai-aghatta Poultry Farm

749. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government have received any representation from the employees of six units at Hesaraghatta Poultry Farm (under jurisdiction of Ministry of Agriculture) to introduce 'salary savings scheme' to enable the employees to deposit their L.I.C. premium directly through banks; and

(b) if so, what are the details thereof and action taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) While Government have received no such representation from the employees, LIC have reported that a proposal in this connection was received by their Bangalore Divisional Office. Under the LIC Salary Saving Scheme premium amounts are to be deducted from the employee's salary and the amounts so deducted every month are required to be paid to the LIC by one cheque by the employer.